

नया वक्फ कानून ऐतिहासिक फैसला: धामी

□ वक्फ की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी
□ मुस्लिम महिलाओं ने किया सीएम का स्वागत



विशेष संवाददाता
देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा लाये गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से अब वक्फ की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा सकेगा और यह जमीन गरीब तथा जरूरतमंद मुसलमानों के काम आ सकेगी और

इसका उपयोग जनहित कार्यों के लिए हो सकेगा।

भाजपा मुख्यालय में आयोजित वक्फ जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस कानून को लाया जाना एक ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने कहा कि हम भाजपा के लोग कानून को मानने वाले लोग हैं तथा जो

भी काम करते हैं कानून के दायरे में रहकर जनहित के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कुछ पहुंच वाले और रसूखदार लोग अवैध तरीके से कब्जा किए बैठे हैं किसी ने फाइव स्टार होटल बना रखा है तो किसी ने कोठी और बंगला बना रखा है लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में वक्फ की जमीन और परिसंपत्तियों में भी

भारी इजाफा हुआ है यह 39 एकड़ से बढ़कर 18 लाख एकड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन और परिसंपत्तियों का बीते समय में राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए भरपूर दुरुपयोग किया जाता रहा है। माफिया और दबंग लोग बड़ी संख्या में इन संपत्तियों पर कब्जा जमाये बैठे हैं तथा यह सब वक्फ संपत्तियों की उचित प्रबंधन व्यवस्था न होने के कारण हुआ है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ

की संपत्तियों का परीक्षण कराया जाएगा तथा अवैध रूप से किए गए कब्जे हटाए जाएंगे और इस जमीन का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए तथा जनहित कार्यों के लिए किया जाएगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस नए कानून की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें उल्लेखित कई प्रावधानों पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई हुई है।

दून वैली मेल

संपादकीय

अंतरिम रोक, अंतरिम राहत

केंद्र सरकार द्वारा जिस वक्फ संशोधन बिल 2025 को एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया के बाद कानून का जामा पहनाया गया उस बिल की संवैधानिक वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार फंसती दिख रही है। कोर्ट में दायर 120 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस कानून को चुनौती देने वालों के अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों का संतोषजनक जवाब न दे पाने में असमर्थ रहे सॉलीसीटर तुषार मेहता ने कोर्ट से इसके लिए अब एक सप्ताह का समय मांगा है जो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा दे तो दिया गया है लेकिन इसके साथ ही इस बिल में किए गए उन तमाम संशोधनों पर अदालत का फैसला आने तक उनके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई जिन्हें लेकर इस बिल की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाये जा रहे थे। इस बिल में जिस वक्फ वार्ड यूजर को किसी भी तरह का बदलाव न करने तथा केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति करने पर रोक लगा दी गई है। सवाल यह है कि जिस बिल पर चार दिन तक संसद में लंबी बहस चली जिसमें जेपीसी ने तमाम संशोधन क्रिया तथा अल्पसंख्यक मंत्री किरन रिजिजू जिन्होंने संसद में 95 लाख सुझाव आवेदनों को पढ़ने तथा तमाम विशेषज्ञों की राय के बाद इस बिल का मसौदा तैयार करने की बात कही थी उस बिल पर सालिसीटर चंद सवालियों का भी संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दे सके? वक्फ परिषद और बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति के मसले पर जब कोर्ट ने पूछा कि क्या वह हिंदुओं के बोर्ड और अन्य धर्म के बोर्डों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने को तैयार है या दंगे तो उनके पास इसका कोई जवाब क्यों नहीं था? खास बात यह है कि इसे लेकर जो सबसे गंभीर सवाल उठ रहा है क्या सरकार बहुमत के दम पर असंवैधानिक कानून बनाने पर आमादा है? सबसे अधिक चिंता जनक है। यह बात इसलिए कहीं जा रही है कि सरकार द्वारा लाये गए इलेक्टोरल बांड और आईटी कानून संशोधन बिल इससे पूर्व असंवैधानिक करार दिए जा चुके हैं। अगर सरकार द्वारा बार-बार संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध कानून लाये जा रहे हैं इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? यह सवाल स्वाभाविक ही खड़े होते हैं कि विपक्ष इसे संविधान बदलने की कोशिश और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त करने का प्रयास बता रहा है तो क्या बेवजह है। इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देने और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर तकरार क्यों हो रही है? जबकि जस्टिस संजीव खन्ना साहब कह रहे हैं कि उनकी मंशा इस बिल पर रोक लगाने की नहीं है लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा है जो किसी के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करता है तो न्यायपालिका अपना काम करेगी। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपनी किसी भी गलत बात को सही साबित करने की अगर जिद ठानी जाती है तो उसे क्या न्यायपालिका को सही मान लेना चाहिए। इसके विरोध में दायर याचिकाओं का काउंटर करने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा समर्थन याचिकाओं का दायर किया जाना हास्यास्पद है। दो दिन की सुनवाई में यह स्पष्ट हो चुका है कि भले ही न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक ठहरा कर रद्द न किया जाए लेकिन सरकार को उन बिंदुओं पर संशोधन करना ही पड़ेगा जिन पर संवैधानिक आपत्तियां हैं। अगर ऐसा होता है तब इस बिल को लाना न लाना दोनों ही बराबर होगा। सप्ताह भर बाद सरकार अपना क्या पक्ष रखती है और कोर्ट क्या आदेश देती है यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल अंतरिम रूप से अंतिम राहत तो मिल चुकी है।

'गुड फ्राइडे' हमें दया और करुणा दिखाने की प्रेरणा देता है: पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'गुड फ्राइडे' के अवसर पर कहा कि यह दिन हमें दया, करुणा और सदैव उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। 'गुड फ्राइडे' ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाये जाने पर उनके बलिदान की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हुए लिखा, गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। यह दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। शांति और एकजुटता की भावना हमेशा बनी रहे।



कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, श्रद्धा, क्षमा, त्याग और सहानुभूति का सार हमारे कार्यों को प्रेरित करता रहे। आइए हम अपने साझा अस्तित्व में मानवता, दया और शांति के मूल्यों को अपनाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, श्रद्धा गुड फ्राइडे हर दिल को करुणा, दया और प्रेम से भर दे तथा सभी के लिए शांति लेकर आए।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन और बलिदान के माध्यम से संपूर्ण मानवता को प्रेम, दया और करुणा के भाव का संदेश दिया था। उनके बताए हुए मार्ग के अनुसरण से समस्त मानव समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

अधिकारी सिर्फ फेसबुक/ रीलस् बनाने में व्यस्त:नेगी

संवाददाता

देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि अधिकारी तो रात-दिन फेसबुक रीलस् बनाने में ही मस्त हैं, उनको नदियों में हो रहे अवैध खनन का खेल दिखाई नहीं देता।

आज यहां जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन- रात नदियों का सीना चीरा जा रहा है, जिसके चलते अवैध खनन का कारोबार पूरी रात भी बे-रोक-टोक चल रहा है, जिसके चलते इस खेल में हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। आलम यह है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ माफिया चला रहे हैं तथा सारे काम माफियाओं के इशारे पर ही हो रहे हैं घ कुछ कर्मठ अधिकारी चाबुक चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी चाबुक के आगे मौन है/ लाचार है। अगर कोई अधिकारी कार्यवाही करना चाहता है तो उसको हासिये पर डाल दिया जाता है। नेगी ने कहा कि माफियाओं के हक में



रातों-रात नीतियों में परिवर्तन हो जाता है तथा उनको फायदा पहुंचाने के लिए/ उनका हक न मर जाए, इसके लिए सरकार बाहर से बड़े-बड़े प्राइवेट नामचीन वकील लाखों रुपए खर्च कर पैरवी के लिए खड़े कर देती है। यहां तक कि सरकार गठन में माफियाओं द्वारा किया गया एहसान उतारने के चक्कर में प्रदेश को खोखला किया जा रहा है। सरकार जिम्मेदार पोस्टों पर सेटिंग- गेटिंग के आधार पर अधिकारियों की तैनाती करती है तथा वहीं इसके विपरीत कर्मठ एवं ईमानदार अधिकारियों को ठिकाने लगाया गया है। नेगी ने कहा कि कमिश्नर

गढ़वाल/ कुमाऊं, जिलाधिकारी एवं पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जी हजुरी में लगे हैं। एक अधिकारी तो रात-दिन फेसबुक रीलस् बनाने में ही मस्त हैं, उनको नदियों में हो रहे अवैध खनन का खेल दिखाई नहीं देता। प्रदेश में हो रहे अवैध खनन के काले कारोबार की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन जिम्मेदार माल काटने में लगे हैं तथा उनको प्रदेश की साख से कोई लेना देना नहीं है। मोर्चा सरकार के काले कारोबार का काला सच जनता के सामने लाकर ही रहेगा। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे।

लघु व्यापार एसोसिएशन ने महिला मोर्चा इकाई का किया गठन



संवाददाता

हरिद्वार। लघु व्यापार एसोसिएशन ने महिला इकाई का गठन श्रीमती कामिनी मिश्रा को अध्यक्ष बनाया।

आज यहां फुटपाथ के कारोबारी रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसो.के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए लघु व्यापार एसो. महिला मोर्चे का अलकनंदा इकाई का गठन करते हुए अध्यक्ष श्रीमती कामिनी मिश्रा महामंत्री गीता देवी कोषाध्यक्ष श्रीमती सीमा देवी उपाध्यक्ष आशा देवी,

ज्योति देवी, राधा देवी, मंत्री इंदिरा देवी प्रचार मंत्री मुन्नी देवी संरक्षक पुष्पा दास, पार्वती देवी सदस्य रूप में गोरी, रिंतु रानी, शांति देवी, बबली, नीलम, पूनम, अरुणा देवी, डोली आदि को नियुक्त किया गया।

इस अवसर पर लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा मां गंगा के घाटों पर बिंदी चूड़ी, माला, फूल प्रसाद, गंगाजली का कारोबार करने वाली महिला स्ट्रीट वेंडर्स की एक बड़ी संख्या है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला सहायता समूह उद्यमिता योजनाएं

चलाई जा रही है लेकिन असंगठित क्षेत्र की महिला स्ट्रीट वेंडर्स को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जो कि अन्याय पूर्ण है। उन्होंने कहा शीघ्र ही घाटों पर बिंदी चूड़ी माला बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली महिला स्ट्रीट वेंडर्स को और संगठित कर शहरी समृद्धि से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। अलकनंदा घाट पर महिला स्टेट वेंडर्स की बैठक में सम्मिलित हुई महिलाओं में मंजू पाल, सुनीता चौहान, निर्मला देवी, संगीता, सुमन गुप्ता, आशा देवी आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

ऋषिराम शिक्षण संस्थान में फायर सर्विस की टीम ने दी अग्नि सुरक्षा जानकारी

संवाददाता

उत्तरकाशी। फायर सर्विस की टीम ने ऋषिराम शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को अग्नि सुरक्षा की जानकारी दी।

आज यहां एकजुट हो, अग्नि सुरक्षित भारत को प्रज्वलित करें की थीम पर आयोजित अग्निशमन सेवा सप्ताह -2025 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी के निर्देशन में फायर सर्विस उत्तरकाशी की टीम द्वारा आज प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, देवेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में ऋषिराम शिक्षण संस्थान, मनेरा में अग्नि सुरक्षा एवं बचाव कार्यक्रम आयोजित कर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं



अध्यापकों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) के संचालन की विस्तृत रूप से जानकारी देने के साथ-साथ आग सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। आग से होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाये और उस

समय क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिये के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल व तेल की आग को बुझाने के गुर सिखाये गए तथा अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी पम्पलेट वितरित किये गये।



मकवाना ने रामपुर तिराहे पर किये शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित

संवाददाता

देहरादून। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने रामपुर तिराहे पर पहुंच शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

आज यहां उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री) भगवत प्रसाद मकवाना ने रामपुर तिराहा शहीद स्मारक जाकर उत्तराखंड के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद स्मारक के निर्माण हेतु भूमि दान करने वाले पण्डित महावीर शर्मा एवं उनके परिवार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री मकवाना ने कहा 2 अक्टूबर 1994 को पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर तत्कालीन केन्द्र की नरसिम्हाराव सरकार एवं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने सुनियोजित तरीके से गोलियां चलवाकर कई आंदोलनकारियों की निर्मम हत्या की और महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने बलात्कार किए। भाजपा की अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने शहीदों एवं आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण किया और उत्तराखंड की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार उत्तराखंड के शहीदों एवं आंदोलनकारियों के हित में कार्य कर रही है। धामी ने रामपुर तिराहा शहीद स्मारक के सौंदर्यकरण हेतु धनराशि जारी की है।

फायर सर्विस की टीम द्वारा जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित

संवाददाता

उत्तरकाशी। फायर सर्विस की टीम द्वारा मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट में अग्नि शमन सुरक्षा एवं बचाव कार्यक्रम आयोजित किया। आज यहां अग्निशमन सेवा सप्ताह -2025 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी के निर्देशन में फायर सर्विस उत्तरकाशी की टीम द्वारा प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, देवेन्द्र सिंह नेगी के नेतृत्व में मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट, गणेशपुर में अग्नि सुरक्षा एवं बचाव कार्यक्रम आयोजित कर औद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों को अग्निशमन के प्राथमिक उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। विद्युत शॉर्ट सर्किट, पेट्रोल, डीजल व अन्य प्रकार की अग्नि दुर्घटनाओं की जानकारी तथा बचाव के साथ अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी पम्पलेट वितरित किये गये।



संगीत विभाग की कार्यशाला आयोजित

संवाददाता

देहरादून। संगीत विभाग की कार्यशाला के तीसरे दिन तीन ताल में निर्मित सादा टुकड़ा आदि की शिक्षा प्रदान की। आज यहां वृंदावन के प्रसिद्ध कथक नर्तक आशीष सिंह (नृत्य मंजरी दास) जी ने कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून के संगीत विभाग द्वारा सप्त दिवसीय कार्यशाला के तृतीय दिवस पर बच्चों ने कथक नृत्य के पारंपरिक प्राचीन परंपरा के अनुसार तोड़े टुकड़े गुरु वंदना नमस्कार का टुकड़ा तिहाई, तीन ताल में निर्मित सादा टुकड़ा आदि की शिक्षा प्रदान की। कथक गुरु आशीष सिंह कहते हैं कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को आगे लाकर नृत्य की तालीम दिलानी चाहिए कार्यशाला में कॉलेज की अध्यापिकाओं ने भी भागीदारी की। कार्यशाला दो भागों में किया जा रहा है। 50 से 60 बच्चों और महिलाओं ने भागीदारी की है। इसमें डॉ हेमन पाठक, डॉ ममता यादव, डॉ सरिता नेगी, डॉ, डॉ प्रवीण चतुर्वेदी, डॉ नीना गुप्ता अर्चना चौहान, डॉ अर्चना डिमरी, डॉ रचना पांडे, डॉ बबीता शर्मा, डॉ सविता, एवं डॉ श्वेता त्रिपाठी उपस्थित थीं।

पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है ग्राम सैदुल का श्रीराम होमस्टे



संवाददाता

टिहरी। सैदुल गांव होम स्टे के रूप में चर्चाओं में आ रहा है। यह होमस्टे देश-विदेश के पर्यटकों की भी पसंद बनता जा रहा है।

आज यहां टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखंड के ग्राम सैदुल के राजेंद्र सिंह चौहान ने अपने ही पैतृक घर को होमस्टे बनाकर बड़ी मिसाल पेश की है। राजेंद्र सिंह होमस्टे के साथ पर्यटकों को विलेज टूर भी कराते हैं और यात्री पर्यटकों को ट्रेकिंग का अनुभव भी देते हैं, जिससे सैदुल गांव होम स्टे के रूप में चर्चाओं में आ रहा है। यह होमस्टे देश-विदेश के पर्यटकों की भी पसंद बनता जा रहा है। वैसे तो जनपद टिहरी में पर्यटक स्थलों की गिनती की जाए तो वह भी कम है।

समिति ने की गैस के मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग

संवाददाता

देहरादून। नेताजी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी देहरादून के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में बिजली और एलपीजी गैस के मूल्य में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने का आग्रह करते हुए समिति ने कहा नेताजी संघर्ष समिति जनहित में आग्रह करती है कि प्रदेश के अंदर बिजली और एलपीजी घरेलू गैस के दामों में जो वृद्धि हो गई है उसे जनहित में वर्तमान महंगाई को देखते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। स्मरण रहे की उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहलाता है और यहां पर बिजली के मूल्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जो की एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। समिति जनहित में आग्रह करती है कि बिजली एवं एलपीजी घरेलू गैस के दामों में जो वृद्धि की गई है उसे वापस लेकर जनता को राहत दिलाई जाए ताकि जनता में जो आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई है वह समाप्त हो सके। ज्ञापन देने वालों में नेताजी संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष प्रभात डंडरियाल, प्रमुख महासचिव आरिफ वारसी, आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती, विपुल नौटियाल, नवनीत गोसाईं, दानिश नूर, सुशील विरमानी, जय बिष्ट, गुलाम मुस्तफा, रणजीत जोशी, संदीप गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

ऐसे में विकासखंड जौनपुर के सैदुल गांव के राजेंद्र सिंह चौहान ने अपने आतिथ्य सत्कार और कौशल से गांव को पर्यटकों के लिए नया ठिकाना बना दिया है। होमस्टे के संचालक राजेंद्र चौहान ने बताया कि उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने गांव के पैतृक घर को होमस्टे बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने होमस्टे को 2023 में पर्यटन विभाग में पंजीकृत करवाया था, जिससे उन्हें आसानी से ऑनलाइन बुकिंग भी मिल रही है। अभी तक उनके श्रीराम होमस्टे में 500 से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। उन्होंने पर्यटकों के लिए विलेज लाइफ की एक नई झलक की सोच के साथ इस होमस्टे की संरचना की थी। राजेंद्र सिंह चौहान की स्वरोजगार की

राह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा है। श्रीराम होमस्टे के आउटलुक के लिए आप सीधे उनके सोशल मीडिया हैंडलर में जाकर फॉलो कर सकते हैं। इस्टाग्राम में 'आर्ट विलेज सैदुल' और फेसबुक में 'सैदुल हेरिटेज विलेज' नाम से उपलब्ध है। श्रीराम होमस्टे में आकर आप कई बुग्याल, माउंटन ट्रेक और केव का आनंद भी ले सकते हैं। जौनपुर विकासखंड के 2 किलोमीटर नाकथात ट्रेक, नाग देवता मंदिर, 5 किलोमीटर दणाच टॉप ट्रेक के साथ हिमालय दर्शन और मसूरी चकराता भी देख सकते हैं। वही आप होम स्टे के पास में पड़ने वाले शिव मंदिर केव, वाटर केव, और टाइगर केव का भी आनंद ले सकते हैं।

बस्तियां उजाड़ने का आरोप..!

संवाददाता

देहरादून। नदी किनारे बसी बस्तियों पर लाल निशान लगाने पर बस्तियों को उजाड़ने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने जन सभा का आयोजन किया।

जाखन चौक पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों मजदूरों ने आवाज उठाया कि प्रशासन और सरकार होटल, रेस्टोरेंट, सरकारी विभागों और अन्य बड़े अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए मजदूरों को बेघर करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट के आदेशों का अपमान करते हुए ऐसे तत्वों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जबकि सबके सामने नदियों में मलबा डाला गया है और नदी पर इन रसूखदारों ने बड़े बड़े निर्माण भी बनाये हैं। दूसरी तरफ उन्ही आदेशों के बहाने मनमानी से बिंदाल नदी किनारे बसे मजदूरों को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।

जाखन क्षेत्र में ही जिन घरों पर निशान लगाए गए हैं, उनमें से कई घर स्पष्ट रूप से 2016 से पहले के हैं। 2024 में भी ऐसी ही एक प्रक्रिया के बाद प्रशासन ने दावा किया था कि रिस्पना नदी पर बस्तियों में 525 अवैध घर हैं। लगातार आवाज उठाने के बाद उनको मानना पड़ा कि इनमें से 400 से ज्यादा वैध ही हैं। सभा में भागीदारी

करते हुए वक्ताओं ने सरकार को याद भी दिलाई कि 17 जनवरी को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक भी मजदूर बस्ती नहीं टूटेगी। लेकिन उस बयान के बाद दो सप्ताह पूरा होने से पहले ही सरकार और प्रशासन पहले एलिवेटेड



रोड के नाम पर और अभी कोर्ट के आदेशों के बहाने लोगों को बेघर करने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसके अतिरिक्त मजदूरों के लिए बनाये गए कल्याणकारी योजनाओं में भी लगातार मनमानी, नाकामी और भ्रष्टाचार दिख रहा है। पिछले छह महीनों से निर्माण मजदूर योजना में पंजीकरण ही नहीं हो रहा है।

सभा में लोगों ने कहा कि इन मुद्दों पर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। जन हस्तक्षेप के बैनर तले आयोजित जन सभा में चेतना आंदोलन से शंकर गोपाल, सुवा लाल, उमेश, सुनीता देवी के साथ गजराज, रमेश कुमार, इरफान इत्यादि शामिल रहे।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान

प्रह्लाद सबनानी

भारत में लगभग 60 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जबकि, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 18 फीसद के आसपास बना हुआ है। इस प्रकार, भारत में गरीबी को समूल नष्ट करना है तो इस क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू करने ही होंगे। भारत ने हालांकि आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलताएं अर्जित की हैं और विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शीघ्र ही अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत विश्व में सबसे अधिक तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, इसके आगे की राह कठिन है क्योंकि केवल सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र के बल पर और अधिक तेज गति से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना होगा। भारत में हालांकि कृषि क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के पास पूंजी का अभाव रहता था और वे बहुत ऊंची ब्याज दरों पर महाजनों से ऋण लेते थे और उनके जाल में जीवन भर के लिए फंस जाते थे, परंतु, आज इस समस्या को बहुत बड़ी हद तक हल किया जा सका है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को आसान नियमों के अंतर्गत बैंकों से पर्याप्त ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ देश के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। दूसरे, इसी संदर्भ में किसान सम्मान निधि योजना भी किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना का लाभ भी करोड़ों किसानों को मिल रहा है। भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति पर काम किया जा रहा है, एवं सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है ताकि खेती में पानी के उपयोग को कम किया जा सके तथा जल संरक्षण के साथ सिंचाई की लागत भी कम हो सके।

देश में सीमांत एवं छोटे किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो गई है। ये किसान किसी तरह अपना और परिवार का भरण-पोषण कर पा रहे हैं। इनके लिए कृषि लाभ का माध्यम नहीं रह गया है। इन तरह की समस्याओं के हल के लिए केंद्र सरकार विभिन्न उत्पादों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर, वृद्धि करती रहती है। इससे किसानों को लाभ हो रहा है। भंडारण सुविधाओं (गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज का निर्माण) में खासी वृद्धि हुई है। परिवहन सुविधाओं में सुधार के चलते किसान कृषि उत्पादों को लाभ पर बेचने में सफल हो रहे हैं। इन सुविधाओं में कमी के चलते किसान कृषि उत्पादों को बाजार में बहुत सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हुआ करता था। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना भारी मात्रा में की जा रही है। इससे कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है। कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने में सफलता मिल रही है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो एवं कृषि उत्पादकता बढ़े। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी किसानों की मदद कर रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार को स्थापित करने के प्रयास जारी हैं ताकि किसान सीधे ही उपभोक्ता को फसल बेच सकें।

कृषि फसल बीमा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सूखे, अधिक वर्षा, चक्रवात, अतिवृष्टि, अग्नि आदि जैसी आपदाओं से प्रभावित फसल के नुकसान से किसान को बचाया जा सके। करोड़ों की संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। खेती किसानों का काम पूरे वर्ष भर नहीं होता। इसलिए किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन निर्मित करने के उद्देश्य से पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि कृषि सहायक क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

दुनिया के प्रमुख खाद्य पदार्थों यथा गेहूं एवं चावल का भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कई सूखे में, कृषि आधारित कपड़े, कच्चे माल, जड़ फसलों, दालों, मछली पालन, अंडे, नारियल, गन्ना एवं कई सब्जियों का बड़ा उत्पादक है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत 80 प्रतिशत से अधिक कृषि उपज फसलों (काफी व कपास जैसी नकदी फसलों सहित) के साथ दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। भारत सबसे तेज विकास दर के साथ पशुधन एवं मुर्गी मांस के क्षेत्र में दुनिया के पांच सबसे बड़े उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। अधिकतम उपभोक्ता तो आज भी ग्रामीण इलाकों में ही रह रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की मांग भी ग्रामीण इलाकों से ही निकल रही है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो सांध्य दून वैली मेल के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

डायबिटीज में फायदेमंद जामुन की गुठली

गर्मी के आखिरी और बारिश की शुरूआत में काले-काले रसीले जामुन हर जगह देखने को मिलेंगे। इन दिनों बाजार में आम के साथ-साथ जामुन की भी बहार आई है।

थोड़े समय के लिए आने वाला जामुन स्वाद में खट्टा मीठा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक जामुन की गुठली का औषधीय महत्व होता है। जिसे हम - आप बेकार समझकर फेंक देते हैं वह आपकी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है? जामुन की गुठली डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

हालांकि डायबिटीज के मरीजों के लिए जामुन एक बेहतर फल माना जाता है। लेकिन डायबिटीज में केवल जामुन ही नहीं, बल्कि जामुन के गुठली का पाउडर भी बेहद फायदेमंद होता है। जामुन के बीज का विभिन्न वैकल्पिक उपचारों में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में डायबिटीज को



नियंत्रित करने के लिए, यूनानी और चीनी दवाओं में पाचन संबंधी रोगों के लिए जामुन के गुठली का उपयोग किया जाता है। यह विटामिन ए और सी का बेहतर स्रोत है।

-जामुन की गुठली से पाउडर बनाना जामुन को धूप में सूखाकर पाउडर बनाने के लिए जामुन खाने के बाद गुठली को अच्छी तरह धो लें। फिर इसे धूप में

अच्छी तरह से सुखाकर इसका छिलका उतार लें। अंदर का हिस्सा आपको पिस्ता की तरह नजर आने लगेगा।

अब इस छिलके के साथ पतला पाउडर लें। लेकिन ध्यान रहें कि सूखने के बाद गुठली सख्त हो जाती है इसलिए गुठली को पीसने से पहले इसके छोटे-छोटे टुकड़े अवश्य कर लें। इसे रोजाना 1 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट गुनगुना पानी के साथ सेवन करें। कुछ ही दिनों में आपकी डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगी।

-अन्य रोगों में भी लाभकारी

जामुन की गुठली के चूर्ण को एक चम्मच मात्रा में दिन में दो-तीन बार लेने पर पेट में आराम मिलता है। रक्तप्रदर की समस्या होने पर जामुन की गुठली के चूर्ण में पच्चीस प्रतिशत पीपल की छाल का चूर्ण मिलाकर, दिन में दो से तीन बार एक चम्मच की मात्रा में ठंडे पानी से लेने से लाभ मिलता है।

दांत और मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए जामुन विशेषतौर पर फायदेमंद होता है। इसकी गुठली को पीसकर, इससे मंजन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। यदि आपका बच्चा बिस्तर गीला करता है तो जामुन की गुठली को पीसकर आधा-आधा चम्मच दिन में दो बार पानी के साथ पिलाने से लाभ मिलता है।



शब्द सामर्थ्य -97

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. कतार, क्रम, पांत 2. लज्जत, जायका 4. कारण, वजह 7. सुंदर प्रतीत होना, सुखद होना 8. घोड़े आदि का मल 9. अक्सर, ज्यादातर 10. चक्की में पीसना, मसलना, कुचलना 12. धनुष, फौजी टुकड़ी 13. आभूषण, जेवर 15. लहरों का चक्कर, जलावर्त, भ्रमर 17. बायां, विरुद्ध 18. गाना, नगमा 19. लाचार, विवश 22.

- नमन, प्रणाम 25. चौकी, थाना 26. इकरार, समझौता, ठेका 27. अधिकार होना, सामर्थ्य होना (मुहा.)।

ऊपर से नीचे

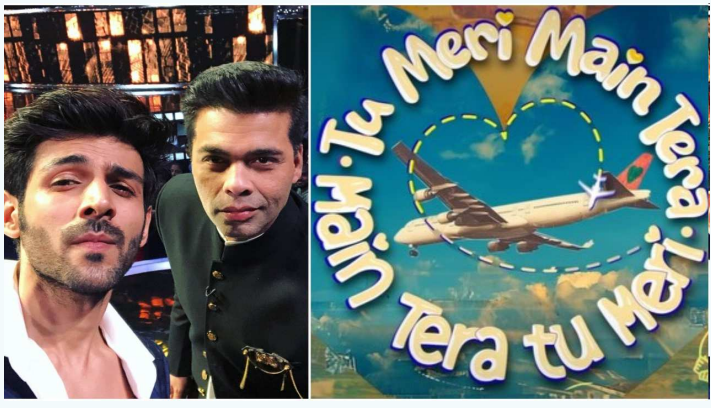
1. एक प्रदेश जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है 2. हविर्दान के समय उच्चारित एक शब्द, भष्म 3. दन-दन करते हुए 5. बलशाली, बलवाला 6. परिवर्तित करना, पहले से भिन्न हो जाना 7. चांद, चंद्रमा, रजनीश 11.

- अप्रिय, अरुचिकर 14. मैं का बहुवचन 15. भंगेड़ी, भंग करने वाला, झाड़ू लगाने तथा मैला साफ करने वाला 16. मातृभूमि, स्वदेश 19. मक्खन, माखन 20. बुढ़ापा, धन, ज्वर 21. टालना, हटाना, बहाना करके हटाना 23. सीमा, हद 24. सौ का पांचवा हिस्सा 25. घोड़े के पैरों में लगाने का लोहे का टुकड़ा, पौधे आदि का डंठल।

1		2	3	4	5	6
		7			8	
9			10		11	
		12		13	14	
15	16			17		
18			19	20		21
		22	23			
				24	25	
26				27		

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 96 का हल

वि	ज	य	ब	नि	या	दे
वा		ती	त	र	रा	जी
ह	मा	म		स	प	ना
		न			टा	
दा	व	त		वि	ना	श
य		ह	त्या		ह	र्जा
रा	ह	त		न	ज	र
	वा				मी	ना
दु	ला	रा		जा	न	की



13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में आएगी तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी फिल्म

कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी वेलेंटाइन डे 2026 के लिए लॉक, रोमांस का जादू बिखेरेंगे रूह बाबा कार्तिक आर्यन और फिल्म मेकर करण फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के लिए फिर से साथ काम कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट आखिरकार तय हो गई है। खबर है कि धर्मा प्रोडक्शंस की आगामी फिल्म में अनन्या पांडे को मुख्य भूमिका में लिया जा सकता है।

करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, भूमिका तिवारी, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा निर्मित रोमांटिक कॉमेडी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज डेट लॉक कर दी गई है। यह फिल्म 2026 में वेलेंटाइन डे वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की रिलीज डेट के बारे में जानकारी साझा की है। तरण आदर्श के मुताबिक, कार्तिक आर्यन वेलेंटाइन 2026 पर आर रहे हैं- तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी की रिलीज डेट लॉक। कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी, जो एक लव स्टोरी है, 13 फरवरी 2026 (वेलेंटाइन डे सप्ताह) को सिनेमाघरों में आएगी। समीर विद्वांस, जिन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म सत्यप्रेम की कथा की थी, फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं।

तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ अनन्या पांडे नजर आ सकती हैं।

जनवरी में, आर्यन और समीर विद्वांस के साथ स्क्रिप्ट-रीडिंग सेशन में अनन्या पांडे का एक वीडियो ऑनलाइन साझा किया गया था। अगर उनकी पुष्टि हो जाती है, तो यह पति पत्नी और वो के बाद आर्यन और अनन्या पांडे दोबारा नजर आ सकते हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। शुरुआत में, अफवाहें उड़ी थीं कि जाह्नवी कपूर को इस भूमिका के लिए चुना जा रहा है।

द पैराडाइज से नानी की नई झलक आई सामने

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता नानी काफी समय से अपनी आगामी फिल्म द पैराडाइज को लेकर चर्चा में हैं, जिसके निर्देशन की कमान श्रीकांत ओडेला ने संभाली है।

दशहरा के बाद यह श्रीकांत और नानी के बीच दूसरा सहयोग है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुधाकर चेरुकुरी इस फिल्म के निर्माता हैं।

अब द पैराडाइज से नानी की नई झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा है।

द पैराडाइज एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसे हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली भाषा में रिलीज किया जाएगा। खास बात यह है कि यह फिल्म अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में भी दर्शकों के बीच आएगी।

यह फिल्म ठीक एक साल बाद यानी 26 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नानी के अलावा इस फिल्म में सोनाली कुलकर्णी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। श्रीकांत ओडेला ने ही फिल्म की कहानी लिखी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म द पैराडाइज का अंदाज जंगली और बेबाक है। श्रीकांत ओडेला ने फिल्म की कहानी 1960 के दशक के एक काल्पनिक शख्स के इर्द-गिर्द लिखी है, जो गरीब और शोषित लोगों के लिए उम्मीद बनकर आया था। फिल्म द पैराडाइज की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। इसे स्पेनिश जैसी अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, ताकि दुनियाभर के लोग इसे देख सकें।



जन्नत फेम सोनल चौहान मिनी ड्रेस में दिए किलर पोज, एक्ट्रेस की हॉटनेस ने बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। 'जन्नत' फेम इस खूबसूरत अदाकारा ने हाल ही में मुंबई में एक ब्रांड लॉन्च इवेंट के दौरान शिरकत की, जहां उन्होंने पिक शॉर्ट आउटफिट में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इवेंट की तस्वीरें जैसे ही इंस्टाग्राम पर सामने आईं, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। सोनल ने ऑफ-शोल्डर, रोज़ फ्लावर स्टाइल की पिक मिनी ड्रेस में कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक कातिलाना पोज़ दिए। उनकी कर्व्स और कॉन्फिडेंस ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया।

यह लुक उन्होंने केटल स्टूडियो चिप्स के लॉन्च पर कैरी किया था, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए ब्रांड को बधाई दी। सोनल का यह बोल्लड और बिंदास अंदाज़ फैशन लवर्स के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा - 'बेहद आकर्षक', 'स्ले क्वीन', और 'हमेशा की तरह भव्य', वहीं कई सेलेब्स ने भी उनके लुक की तारीफ की।

गौरतलब है कि सोनल चौहान ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 'जन्नत' फिल्म से बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री की थी। आज भी उनकी खूबसूरती और स्टाइल का कोई जवाब नहीं। फैंस उनके आगामी प्रोजेक्ट का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं।



ऋतिक रोशन की फिल्म कृष 4 से जुड़ीं नोरा फतेही



जगत में बतौर निर्देशक कदम रखने जा रहे हैं।

ताजा खबर यह है कि कृष 4 की स्टार कास्ट में जानी-मानी अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही शामिल हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कृष 4 में अहम भूमिका निभाने के लिए निर्माताओं ने नोरा से संपर्क किया है।

दिलचस्प बात यह है कि उन्हें फिल्म की कहानी पसंद आ गई है और कृष 4 का हिस्सा बनने के लिए वह काफी उत्साहित हैं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रीति जिंटा भी कृष 4 में नजर आएंगी। उन्होंने कोई मिल गया में निशा की भूमिका निभाई थी। अब वह अपने इस किरदार को दोबारा दोहराती दिखेंगी।

कृष फ्रैंचाइजी की पहली फिल्म थी कोई मिल गया जो 2003 में आई थी। इसने बॉलीवुड को एक नया सुपरहीरो दिया था।

इसके बाद साल 2006 में कृष और 2013 में कृष 3 रिलीज हुईं। कृष में प्रियंका चोपड़ा, रेखा और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे, वहीं कृष 3 में कंगना रनौत, विवेक ओबेरॉय और राजपाल यादव जैसे कलाकार नजर आए थे।

इस सीरीज की पिछली तीनों फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है।

जब से ऋतिक रोशन ने अपनी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी कृष की चौथी किस्त की घोषणा की है, प्रशंसकों का उत्साह

चरम पर है। खास बात यह है कि कृष 4 के निर्देशन की कमान ऋतिक को सौंपी गई है। इस फिल्म के जरिए वह मनोरंजन

वक्फ संशोधन के विरुद्ध याचिकाओं की प्रतिस्पर्धा शुरू

अवधेश कुमार
वक्फ संशोधन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। इस संशोधन के दोनों सदनों में पारित होने के अगले दिन से ही उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं जाने लगीं। एक साथ तीन तलाक, नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरुद्ध भी हमने यही देखा। इन सभी मामलों की न्यायिक परिणति देश के सामने है।

हमारे सामने दो दृश्य भी हैं। लोक सभा में बहस के पूर्व सभी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया था। राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट घोषणा की कि सांसद स्वतंत्र हैं, व्हिप नहीं है, वे जैसे चाहें मतदान करें। इसके बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या से ज्यादा मत विधेयक के समर्थन में आए। इसके कोई निहितार्थ हैं या नहीं? दोनों सदनों में बहस और मतदान के दौरान देश में समर्थन और विरोध, दोनों में मुसलमान उतरे। उन दो दिनों में समर्थकों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं और संगठनों ने खुल कर विधेयक का समर्थन किया। इनमें वे मुस्लिम मजहबी नेता और संस्थाओं के प्रमुख भी शामिल थे जो पहले वक्फ में किसी प्रकार के संशोधन का घोर विरोध करते थे।

ऐसे विषयों पर सुधार और परिवर्तन के संवैधानिक कानूनी कदमों के विरुद्ध प्रचार और रोकने की कोशिश पहली बार नहीं है। वक्फ कानून, उससे संबंधित बोर्ड और ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण को मुस्लिम वोट पाने की नीति के तहत सुपर सरकार, सुपर प्रशासन और सुपर न्यायपालिका की

भूमिका दे दी गई थी, उस ढांचे में लाभान्वितों तथा आनंद सुख भोगने वालों के अंदर छटपटाहट स्वाभाविक है। वक्फ कानून में संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए था या संशोधन में क्या असंवैधानिक, इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी है, इसका तथ्यात्मक उत्तर विपक्ष के किसी नेता द्वारा संसद में नहीं मिला। जब एक सदस्य ने कहा कि मुसलमान कानून को नहीं मानेगा तब गृह मंत्री ने कहा कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है, सबको मानना पड़ेगा। संसद द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत पारित कानून भारत के सभी क्षेत्रों और व्यक्तियों पर लागू होता है। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने लोक सभा में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया को बहुमत के द्वारा संविधान का अतिक्रमण और लोकतंत्र का गला घोटने के समान बता दिया।

लोक सभा में अमित शाह ने रिकॉर्ड रखते हुए बताया कि संप्रग सरकार ने 2013 में चार घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पास कर दिया था जबकि इस बार दोनों सदनों में करीब 27 घंटे से ज्यादा का समय लगा। वक्फ ने जिस तरह पूरे देश में संपत्तियों का दावा किया, कब्जे में लिया उसकी अनेक कथाएं रिकॉर्ड में सामने हैं। यह कैसी संवैधानिक व्यवस्था थी जिसमें वक्फ किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल बरसों लगा देगा और फैसले को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते यानी आपकी संपत्ति गई। इसमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों के साथ सार्वजनिक सरकारी संपत्तियां भी शामिल हैं। गृह मंत्री ने सदन में रिकॉर्ड पर कहा कि

कोई गांव या शहर से बाहर नौकरी करने चला गया और उसकी संपत्ति वक्फ कर दी गई। वक्फ में कोई बदलाव नहीं है। किंतु हम अपनी संपत्ति वक्फ में रजिस्ट्री करा सकते हैं, दूसरे की संपत्ति पर कैसे दावा कर सकते हैं? सरकार कैसे संपत्ति वक्फ कर सकती है? यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सच्चर आयोग की नियुक्ति और उसकी रिपोर्ट के बाद पूरे देश में अलग से इस्लामी ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक संपत्ति वक्फ बोर्डों को दी। हमारी, आपकी या किसी मंदिर की जमीन के कागजात, राजस्व आदि का विषय जिला कलेक्टर के अधीन होगा किंतु वक्फ का नहीं हो तो कैसे इसे कानून का पालन माना जाएगा? वक्फ इस्लाम का अंग है, लेकिन भारत के संविधान और कानून के तहत सरकारों द्वारा गठित वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल इस्लाम का विषय नहीं हो सकता। उसे संविधान और कानून के अंतर्गत ही काम करना होगा। कोई संपत्ति जिस उद्देश्य के लिए वक्फ हुई, उसका उपयोग उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं तथा वक्फकर्ता ने? स्वेच्छा से ऐसा किया या दबाव डाल कर कराया गया इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रशासन की है। जिस संस्था में लगभग 41 हजार विवाद हैं और उनमें 10 हजार मुसलमानों द्वारा किए गए उदाहरण नहीं रखा जा सकता था।

वास्तव में वक्फ कानून में संशोधन एक लोकतांत्रिक और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, मजहब का अंग न होते हुए भी इस्लाम के नाम पर कुछ शक्तिशाली प्रभुत्वशाली मुस्लिम पुरुषों के एकाधिकार

और निरंकुश ढांचे को ध्वस्त कर वक्फ की मूल सोच के अनुरूप संविधान की परिधि में लोकतांत्रिक चरित्र में परिणत करने का प्रगतिशील कदम है। ऐसे ढांचे को संसदीय व्यवस्था के तहत ध्वस्त करना, जिसको सरकारें बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए भी स्पर्श करने तक से डरती रही हों, निस्संदेह साहसिक, ऐतिहासिक और युगांतरकारी कदम है। वक्फ की संपत्ति पर इस्लाम की मान्यता के अनुसार गरीब विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा अनाथों का अधिकार है। वक्फ बोर्ड में आपको सामान्य मुस्लिम परिवार के सदस्य शायद ही मिलेंगे। अब इस दौर का अंत होगा तथा गरीब, वंचित, पसमांदा, महिलाएं सब इस्लाम की धारणा के अनुसार वक्फ के उचित उपयोग में भूमिका निभा सकेंगे। वक्फ ने पुराने मामलों के संदर्भ में बदलाव नहीं किया है लेकिन जिन पर विवाद है वे कायम रहेंगे। रिकॉर्ड में और ऑनलाइन आते ही सब पारदर्शी होगा। तो वक्फ के नाम पर हुए अन्याय के निराकरण का रास्ता प्रशस्त होगा और पीड़ितों को न्याय प्राप्त होने की उोस संभावना बनेगी। ऐसे मामलों का सच देश के सामने होगा और इस्लाम के नाम पर हंगामा खड़ा करने वालों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। भूमि या ऐसे मामले राज्यों के विषय हैं। तो अलग-अलग राज्यों का तंत्र सरकारों की राजनीतिक नीति के अनुसार काम करेगा और इनमें समस्याएं आएंगी। किंतु वक्फ के दावों के विरुद्ध पीड़ित को न्यायालय जाने से कोई नहीं रोक सकता। और सिविल न्यायालय में व्यक्ति की पहचान और कानून के अनुसार ही फैसला होगा।



मुनव्वर फारुकी की फर्स्ट कॉपी का प्रीमियर अमेजन एमएक्स प्लेयर पर होगा

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी काफी समय से अपनी वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं।

खास बात यह है कि यह मुनव्वर के करियर की पहली सीरीज है, जिसकी दर्शक लंबे समय से राह देख रहे हैं।

अब निर्माताओं ने फर्स्ट कॉपी का टीजर जारी कर दिया है, जिसे प्रशंसक खूब पंसद कर रहे हैं। मुनव्वर की अदाकारी की भी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं।

फर्स्ट कॉपी का प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर पर होगा। इस सीरीज को आप जून, 2025 में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में देख पाएंगे। फिलहाल सीरीज की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है।

अमेजन एमएक्स प्लेयर ने टीजर साझा करते हुए लिखा, नकली माल की असली दमदार कहानी लेकर हम आ रहे हैं।

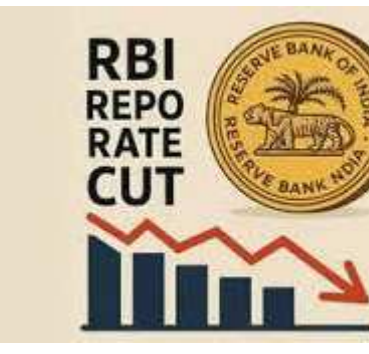
मुनव्वर के अलावा इस सीरीज में गुलशन ग़ोवर, मेयांग चांग, साकिब अयूब, क्रिस्टल डिस्जूजा और आशी सिंह जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

रेपो रेट कम करके आरबीआई ने राहत दी

सुनील विनोद
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी त्रैमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करने के बाद रेपो रेट में कमी की है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में तत्काल प्रभाव से 0.25 फीसदी की कटौती का फैसला सर्वसम्मति से लिया है। दरअसल आरबीआई ने लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती का एलान किया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से अमेरिका की ओर से लगाए गए पारस्परिक शुल्कों से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा

मिलने की उम्मीद बढ़ी है। ब्याज दरों में कटौती के बाद प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट घटकर 6 प्रतिशत हो गई। इस कदम से आवास, ऑटो और कॉर्पोरेट ऋण लेने वालों को राहत मिली। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसका कारण यह है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत सहित 60 देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, यह घोषणा 9 अप्रैल से प्रभावी है। अमेरिका ने भारत के झींगा, कालीन, चिकित्सा उपकरणों और सोने के आभूषणों सहित विभिन्न उत्पादों पर 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया है। यह 26 प्रतिशत शुल्क अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त है। अमेरिका के इस कदम से खास तौर पर निर्यात के मामले

में भारतीय उत्पादकों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। इस वजह से बाजार में भय व्याप्त है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कमी करके बाजार को राहत देने की



कोशिश की है। यह ध्यान रखना होगा कि जब भी रेपो रेट कम होता है तो कर्ज सस्ते होते हैं। जब कर्ज सस्ते होते हैं तो बाजार में तरलता बढ़ती है। तरलता बढ़ती है तो मुद्रा का प्रवाह गतिमान रहता है जिसका लाभ अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। इसी के साथ वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास अनुमान को भी 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 कर दिया है। यह अनुमान घटा जरूर है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ है, कि बहुत चिंता की जाए। बहरहाल, उम्मीद है कि आरबीआई के इस कदम से बाजार को स्थिरता मिलेगी और निर्यातकों को इस नई आर्थिक चुनौती से निपटने की शक्ति मिलेगी।

रेपो दरों में कमी आती है तो इससे भारतीय बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। यही कारण है कि इसे एक समयोचित निर्णय माना जा रहा है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय से खुदरा बाजार में महंगाई पर नियंत्रण लगा है। सब्जियां, फलों और अनाज की कीमतों में लगातार बढ़ाव हुआ है। इससे खुदरा महंगाई दर कंट्रोल में आई है। तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि आरबीआई रेपो दरों में कटौती कर सकता है और

उम्मीद के अनुसार आरबीआई ने पहले फरवरी में और अब अप्रैल में लगातार दो बार रेपो दरों में कटौती की है। निश्चित रूप से ब्याज दरों में कमी से बाजार में खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। ईएमआई के कम होने से ग्राहकों को महंगाई की मार से बचाने और बचत को दूसरी वस्तुओं की खपत में लगाने में मदद मिलेगी। जाहिर है वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में घरेलू मांग बढ़ाने के लिए यह कदम लाभकारी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने के फैसले से यह जाहिर होता है कि देश का सर्वोच्च नीति निर्धारक बैंक और केंद्र सरकार अमेरिका द्वारा उत्पन्न की गई नई चुनौतियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

सू- दोकू क्र.97									
	7			1		3			
1		9				5			
			3					1	
		5							3
3					2		5		
				3					2
	4								7
7		8		1		6			
	6		7		9				1

नियम

- कुल 81 वर्ग है, जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
- हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
- बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.96 का हल									
5	2	4	9	6	7	8	1	3	
3	6	7	4	1	8	2	9	5	
8	1	9	3	2	5	4	6	7	
6	3	5	1	9	4	7	2	8	
7	9	8	5	3	2	6	4	1	
2	4	1	7	8	6	5	3	9	
4	5	3	6	7	9	1	8	2	
9	8	6	2	5	1	3	7	4	
1	7	2	8	4	3	9	5	6	



राज्य के तीन लाख से अधिक किसानों की बदलेगी किस्मत

संवाददाता

देहरादून। राज्य सरकार किसानों को परम्परागत खेती के बजाय नगदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जिससे कुल मिलाकर 3 लाख 17 हजार से अधिक किसान लाभांशित होंगे।

राज्य सरकार किसानों को परम्परागत खेती के बजाय नगदी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में राज्य कैबिनेट ने बीते दिनों मिलेट्स पॉलिसी, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना पर मुहर लगाई है, जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख 17 हजार से अधिक किसान लाभांशित होंगे। उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने 2030-31 तक 11 पर्वतीय जिलों के लिए कुल 134.89 करोड़ रुपए की कार्ययोजना पर मुहर लगाई है। इसमें मण्डुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीना उत्पादक किसानों को बीज एवं जैव उर्वरक पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, साथ ही कृषकों को मिलेट की बुवाई करने पर पंक्ति बुवाई पर रु 4000 प्रति हैक्टेयर और सीधी बुवाई पर रु 2000 प्रति हैक्टेयर की प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

मिलेट पॉलिसी के तहत प्रत्येक वर्ष विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 02 कृषक / समूह को पुरस्कार किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर 01 मिलेट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी। योजना के तहत 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ देने का लक्ष्य है। सरकार इसके तहत श्रीअन्न फूड पार्क की स्थापना भी करेगी। इसी तरह उत्तराखण्ड कीवी नीति के तहत वर्ष 2030-31 तक राज्य सरकार कीवी उद्यान स्थापना के लिए कुल लागत 12 लाख प्रति एकड़ का 70 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करेगी। जिसमें 30 प्रतिशत लाभार्थी का अंश होगा। यह नीति भी हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर राज्य के शेष 11 जनपदों में लागू होगी। कीवी पॉलिसी के अन्तर्गत कुल रु 894 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गई है, नीति के तहत 3500 हैक्टेयर क्षेत्रफल को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें करीब 17500 किसान लाभांशित होंगे। अभी राज्य के लगभग 683 हैक्टेयर के क्षेत्रफल में 382 मैट्रिक टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट खेती योजना के उधमसिंहनगर, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को आधुनिक / वैज्ञानिक पद्यति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।

योजना के तहत वर्ष 2027-28 तक 15 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे 450 किसान लाभांशित होंगे। प्रस्तावित योजना में उद्यान स्थापना के लिए 08 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत राजसहायता का प्राविधान है एवं शेष 20 प्रतिशत कृषक द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के लगभग 35 एकड़ क्षेत्रफल में 70 मैट्रिक टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जा रहा है।

मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई कुमायूँ क्षेत्र अल्मोड़ा को उनके मूल विभाग वापस भेजा !

अल्मोड़ा। पीएमजीएसवाई के कार्यों में उदासीनता बरतने एवं बिना सूचना कार्यालय में अनुपस्थित रहने पर एस.एन.सिंह मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई कुमायूँ क्षेत्र अल्मोड़ा को उनके मूल विभाग सिंचाई विभाग को वापस किया गया है। सचिव ग्राम्य विकास के निर्देश पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू.आर.डी.ए श्री हिमांशु खुराना ने आदेश जारी किया है। अग्रिम आदेशों तक अधीक्षण अभियन्ता पीएमजीएसवाई वृत्त ज्योलीकोट द्वारा अपने कार्यों के साथ मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई कुमायूँ क्षेत्र का कार्यभार संभालेंगे।

मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई कुमायूँ क्षेत्र अल्मोड़ा द्वारा कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने, पर्यवेक्षण की कमी, अधिनस्थ कार्मिकों पर प्रभावी नियंत्रण के अभाव और मुआवजा वितरण की कार्यवाही में धीमी प्रगति के कारण यह कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुमायूँ क्षेत्र के विभिन्न मोटर मार्गों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी।

दुन्या आरा सलपड़ मोटर मार्ग गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने पर विनोद कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, ज्ञानेश चंद्र उपाध्याय, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता और के.एन सती सहायक अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। "एम.आर.एल 18 कसियालेख बुदिबाना सूपी" मोटर मार्ग गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने पर मीना भट्ट अधिशासी अभियन्ता और संजय तिवारी, सहायक अभियन्ता, पीएमजीएसवाई लोनिवि खण्ड, काठगोदाम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी को 02 दिवस के अन्दर सन्तोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मसूरी ग्रीष्मकालीन पर्यटन को सुगम, सुखद बनाना हमारा दायित्व: डीएम

संवाददाता

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मसूरी ग्रीष्मकालीन पर्यटन को सुगम, सुखद बनाना हमारा दायित्व है।

आज यहां सीएम के निर्देशानुसार मसूरी ग्रीष्मकालीन पर्यटन को सुगम बनाने डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार है। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारी इंगो छोड़ प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन व समन्वय में नजर आए। डीएम सविन बंसल, डीएम नैनीताल रहते रूसी बाईपास पर हजारों गाड़ियों की शटल पार्किंग व शटल सेवा का अद्वितीय सफल प्रयोग करवा चुके हैं। जिलाधिकारी ने 163 बीएनएसएस(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने की निर्देश दिए।

उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है तथा कहा कि कोशिश हो कि प्रशासन को विधिक बल इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। वहीं मसूरी सैटेलाइट पार्किंग, गोल्फ कार्ट व शटल सेवा, के साथ पर्यटकों के स्वागत को तैयार है, जिसमें हाथी पांव, किंग क्रैग, कुठाल गेट पर सुरक्षित सैटेलाइट पार्किंग, हाईटेक शटल सेवा व मॉल रोड पर गोल्फ कार्ट शामिल हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि खानापूर्ति लचर प्रणाली छोड़ कानून शांति व्यवस्था के लिए 19 अप्रैल से ध



रा-163 लागू रहेगी, जिसके आदेश जारी किए गए हैं। ग्रीष्मकालीन पर्यटन को लेकर जिला प्रशासन चौकन्ना, आदेश जारी, उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई होना तय है।मॉल रोड एंटी गेट पर डिजिटल रिसिप्स, सैटेलाइट पार्किंग, शटल सेवा व गोल्फ कार्ट जैसी आधुनिक सुविधा डीएम सविन की देन है, जिससे मसूरी में सम सुविधा पर्यटकों को मिल रही है। वहीं प्रशासन पर्यटकों को हाईटेक, सुगम सुविधा और सुरक्षा, जाम से छूटकारा दिलाने को कसर कस ली है। डीएम ने शीतकालीन भांति पर्यटन सुविधाओं और सेवाओं को करें, तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए हैं। ग्रीष्मकाल में मसूरी शहर में अत्यधिक पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आवागमन के दृष्टिगत यातायात, कानून एवं शांति

व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने 19 अप्रैल, 2025 से धरा-163 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लोनिवि के अधिशासी अभियन्ता, आरटीओ, नगर पालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक नगर, देहरादून एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने हाथी

पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट, एवं कुठालगेट पर अस्थायी पार्किंग तथा किंग्रेग पर स्थायी सैटेलाइट पार्किंग विकसित करने और पार्किंग स्थलों को वाहन के अनुसार विभाजित करते हुए व्यवस्थित रूप से वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए हैं। सभागीय परिवहन अधिकारी को शटल सेवा के माध्यम से आने वाले पर्यटकों की संख्या, शटल सेवा प्रदाता द्वारा निधिरित फेरों के दौरान परिवहन किए गए यात्रियों की संख्या का पूरा ब्यौरा रखने के साथ ही शटल सेवा हेतु माल रोड एवं पार्किंग स्थलों पर बूथ संचालन, टिकट काउंटर, पर्याप्त शटल वाहन की उपलब्धता तथा शटल सेवा संचालक की नियमित मॉनिटरिंग करने के आदेश जारी किए गए हैं।

कमानी टूटने से बस सड़क पर पलटी, एक घायल

संवाददाता

देहरादून। आज प्रातः सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना मसूरी को सूचना मिली कि पानी वाला बैंड के पास एक बस रोड पर पलट गई है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मसूरी पुलिस फोर्स के आपदा उपकरण के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर एक 27 सीटर बस रोड पर पलटी हुई थी, जिसमें कुल 27 लोग सवार थे। घटना के संबंध में जानकारी

करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त बस रात्रि 11 बजे कश्मीरी गेट दिल्ली से मसूरी के लिए चली थी, जिसे जसवंत पुत्र शमशाद निवासी विजय पार्क मौजपुर दिल्ली चला रहा था। प्रातः पानी वाला बैंड के पास अचानक बस की कमानी टूटने के कारण वह अनियंत्रित होकर रोड पर ही पलट गई। बस काफी धीमी रफ्तार से चल रही थी, घटना में बस में बैठे एक यात्री अर्चित शुक्ला पुत्र गिरीश चंद

शुक्ला निवासी दिल्ली को मामूली चोटें आई हैं, जिसको 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। शेष सभी बस सवार सुरक्षित हैं, जिनको प्राइवेट वाहनों से मसूरी भेजा गया है। बस को मुख्य मार्ग से हटाकर किनारे किया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से बस की दोनों तरफ पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, मौके पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।

फैक्ट्री में हुई चोरी की घटना का खुलासा, तीन गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने फैक्ट्री में हुई चोरी का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसारथाना डोईवाला पर धर्मेन्द्र सिंह नेगी मैनेजिंग डायरेक्टर देव भूमि इन्टरप्राइजेस मौजा कुआंवाला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी कंपनी देवभूमि इन्टरप्राइजेस के गोदाम से अज्ञात लोगों द्वारा चोरी की गयी तथा फैक्ट्री में घुसकर तारों, अर्थिंग रॉड, लाईटिंग व सोलर पैनल को भी हानि पहुंचाई गयी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना के खुलासे तथा चोरों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये



गठित टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को चैक करते हुए घटना में शामिल संदिग्धों की फुटेजों को प्राप्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चौधरी फार्म हरवाला, डोईवाला से 03 लॉगों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से फैक्ट्री में चोरी किये गए उपकरण व तार/एंगल आदि

बरामद किये गए। पृष्ठताछ में उन्होंने अपने नाम अमन पुत्र वेजनाथ निवासी कुआंवाला हरवाला, सचिन पुत्र अनिल राणा निवासी कुआंवाला हरवाला, अंकित पुत्र प्रमेन्द्र निवासी गोहावर अल्लू थाना चांदपुर, जिला बिजनौर, हाल निवासी-वेद लाला का मकान ग्राम नकरौंदा नियर विष्णुपुरम, डोईवाला बताया। पृष्ठताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वे तीनो नशा करने के आदी है तथा अपने नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके द्वारा उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। सचिन व अमन चिन्हित स्थानों से चोरी करते है तथा चोरी किया गया माल अंकित जो कि कबाडी का कार्य करता है, को लाकर बेच देते है, अंकित उक्त दोनो से माल खरीदकर चोरी किये गये माल को आगे बेचने का कार्य करता है।

राज्यपाल ने किया 'स्कूल डैश-बोर्ड' का लोकार्पण



संवाददाता

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) राज्य के सभी विद्यालयों के लिए निर्मित 'स्कूल डैश-बोर्ड' का लोकार्पण किया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के 13 केंद्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की।

आज यहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव-2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस दौरान स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत कर शिक्षण सामग्री वितरित की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के

सभी विद्यालयों के लिए निर्मित 'स्कूल डैश-बोर्ड' का लोकार्पण किया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के 13 केंद्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। राज्यपाल के निर्देश पर यूटीयू द्वारा राज्य में स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों की सम्पूर्ण जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत स्कूल डैश-बोर्ड तैयार किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के 13 जिलों में स्थित 16055 राजकीय विद्यालयों के सम्पूर्ण विवरण के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के साथ-साथ डैशबोर्ड के एडमिन को अपने लॉग-इन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होने एवं उन्हें देखने की सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में डैशबोर्ड पर 13 जिलों के

95 ब्लॉक में 16055 विद्यालयों में अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्रों/शिक्षकों के साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं का विवरण अपलोड किया जा चुका है, जिसे सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा यथा आवश्यकतानुसार अपने लॉग-इन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे उत्तराखण्ड के लिए आज का यह अवसर विशेष है। उन्होंने कहा कि 'स्कूल डैश-बोर्ड' का लोकार्पण न केवल उत्तराखण्ड की शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी नवाचार का प्रतीक है, बल्कि यह राज्य के हर बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। राज्यपाल ने 'स्कूल डैशबोर्ड' को साकार करने के लिए वीर माधो सिंह भण्डारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तकनीकी विशेषज्ञों, और सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि यह केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह उत्तराखण्ड की शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी क्रांति की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक भी है। राज्यपाल ने राज्य के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय को जिनमें छात्रावासों में रहकर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, को एक अनुपम पहल बताया।

चार शिकारी गिरफ्तार



नील गाय का मांस व हथियार बरामद

हमारे संवाददाता हरिद्वार। जंगली जानवारों का शिकार कर उनके मांस की तस्करी करने वाले 4 शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से 220 किलो नील गाय का मांस, मांस काटने के हथियार व तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद की गयी है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज थाना लक्सर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शिकारी जो जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार कर उसके मांस को तस्करी कर लाते हैं, क्षेत्र में आने वाले हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार आती हुई दिखायी दी। पुलिस ने जब उसे रूकने का इशारा किया तो कार चालक कार मोड़कर

भागने लगा। इस पर उसे घेर कर रोका गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें चार लोग मौजूद मिले जिनके पास से 220 किलो नीलगाय का मांस व मांस काटने के उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम आजम अली पुत्र इसरार अली निवासी बडा बगड सुल्तानपुर कोतवाली लक्सर हरिद्वार, इरशाद पुत्र अशरफ अली निवासी ढाब मौहल्ला सुल्तानपुर कोतवाली लक्सर हरिद्वार, फ़ैसल पुत्र इकबाल निवासी बडा बगड सुल्तानपुर, कोतवाली लक्सर हरिद्वार व मोहब्बत मलिक पुत्र मिदा हसन निवासी ढाब मौहल्ला, सुल्तानपुर, कोतवाली लक्सर हरिद्वार बताया। पुलिस ने उनके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

नहर में महिला ने लगायी छलांग, जलवीर ने बचाई जान

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। आत्महत्या के इरादे से एक महिला ने नहर में छलांग लगा दी गयी। हालांकि मौके पर मौजूद जलवीर ने उसे नहर से निकाल कर उसकी जान बचा ली। महिला पारिवारिक क्लेश के कारण आत्महत्या करना चाह रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर महिला को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया है।



जानकारी के अनुसार आज सुबह एक महिला सोलानी नदी पुल के पास पहुंची और देखते ही देखते उसने पुल से नहर में छलांग लगा दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता महिला नहर में डूबने लगी। वहीं लोगों ने शोर मचाया तो मौके पर मौजूद जलवीर मोनू नहर में कूदा और उसने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो महिला के पास मौजूद आधार कार्ड से उसकी पहचान किशनपुर निवासी के रूप में हुई। बताया गया है महिला का पति से कुछ विवाद चल रहा है जिसके कारण वह मानसिक रूप से तनाव में थी और आत्महत्या के इरादे से नहर में कूद गई। वहीं पुलिस ने महिला के परिजनों से संपर्क कर उसे उनके सपुर्द कर दिया है।

दो बच्चों के बाप ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज

हमारे संवाददाता

नैनीताल। हवस के पुजारी दो बच्चों के बाप ने दूसरे समुदाय की एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं आरोपी ने किशोरी का मोबाइल छीन लिया और सोशल मीडिया पर उसकी इंस्टाग्राम आईडी से छेड़छाड़ कर डीपी पर अपशब्द लिख दिए। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार बनभूलपुरा में रहने वाली 15 वर्षीय पीड़िता की मां ने वनभूलपुरा थाने में तहरीर देकर बताया गया कि आरोपी गौलापार निवासी दो



बच्चों का पिता रिंकू है। आरोप है कि रिंकू और उसकी बेटी की मुलाकात पिछले वर्ष अप्रैल में कालीचौड़ मंदिर के पास हुई थी। रिंकू से पीड़िता की दोस्ती पीड़िता की ही सहेली ने कराई थी। जिसके बाद दोनों के मिलने-जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। बताया कि आरोपी ने बेटी को पहले गौलापार के

एक होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद रोडवेज स्टेशन के पास होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि कुछ दिन पहले किशोरी घर से बाजार जा रही थी। आरोपी ने उसे रास्ते में घेर लिया और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद उसने किशोरी के इंस्टाग्राम आईडी से उसकी फोटो अपलोड कर लिख दिया कि ये दो हजार रुपये में बिकती है। पीड़िता की मां का आरोप यह भी है कि पूर्व में आरोपी कि शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी और तब पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करा दिया था। बहरहाल पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गयी है।

पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के मुख्य बुकी को किया गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस व एसओजी की टीम ने क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा लगाते एक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सट्टे में प्रयोग होने वाली सामग्री बरामद कर ली। पुलिस ने उसके खाते में जमा दो लाख रुपये भी फ्रीज करा दिये।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसपी अजय सिंह को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि मोहब्बेवाला में एक व्यक्ति आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहा है। प्राप्त सूचना पर एसएसपी0 देहरादून द्वारा एसओजी व कोतवाली पटेलनगर की टीम गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये। पुलिस टीम द्वारा सूचना संकलन कर मोहब्बेवाला में दबिश दी गयी तो

अखिल बंसल को प्रतिबन्धित गो एक्सचेंज एप्प के माध्यम से आईपीएल की मुम्बई तथा सनराईज हैदराबाद की क्रिकेट टीमों के मध्य चल रहे मैच में ऑन लाईन सट्टा खिलवाते हुये पाया गया। पुलिस द्वारा मौके से उसको गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन, एक रजिस्टर बरामद किया गया। आरोपी के बैंक अकाउंट की जानकारी करने पर उसके एकाउंट में सट्टे से कमाये हुये 2 लाख रुपये जमा होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाया गया। आरोपी से बरामद रजिस्टर में सट्टे के कारोबार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ में अखिल बंसल द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा गोएक्सचेंज नाम के एप्प में अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला है, जहाँ से वो पैसों में प्वाइंट खरीदता है

तथा उन प्वाइंट के माध्यम से अलग-अलग छोटे सटोरियों/पंटर आदि से सट्टा खिलवाता है। अपनी आईडी से गो एक्सचेंज का लिंक देकर अन्य लोगों से भी आईडी पासवर्ड बनवाते हैं। इसके बाद अपने प्वाइंट उनको पैसों में बेचते हैं। रूपयों का आदान प्रदान गूगल पे के माध्यम से करते हैं, मैच में जीती हुई धनराशि को वह जीतने वाले व्यक्ति को ऑन लाईन वापस देता है। खरीदे गये प्वाइंट के जरिये क्रिकेट मैच में सट्टा खेला जाता है। सट्टा हर बॉल पर, प्रत्येक ओवर पर, टीम की हार-जीत पर, नो बॉल, व्हाइट बॉल पर, फोर व सिक्स लगने पर तथा अन्य प्रकार से खेला जाता है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आर.एन.आई.- 59626/94
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटेघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटेर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटेर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।